ई संदेश

03 सितम्बर, 2026 | अंक - 221

सात दिन, सात पृष्ठ

- उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप पावरहाउस बनाएगी डबल इंजन सरकार: मुख्यमंत्री
- रक्षाबंधन पर्व: बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से सशक्त बनता उत्तर प्रदेश
- ज्ञान, शोध और नवाचार का एकीकृत केंद्र बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय: मुख्यमंत्री
- देवरिया में 305 करोड़ रुपये की लागत वाली 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
- मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण किया और स्थायी समाधान के दिए निर्देश
- विकास की सतत प्रक्रिया पर गोरखपुर : 130 करोड़ रुपये की 170 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास
- बारह संकल्पों के साथ लखनऊ छावनी में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास
- बहराइच-नानपारा-नेपालगंज रोड रेलखण्ड के ब्रॉड गेज का लोकार्पण एवं 04 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारम्भ
- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारम्भ

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप पावरहाउस बनाएगी डबल इंजन सरकार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 अगस्त, 2026 को लखनऊ स्थित लोक भवन में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप ईकोसिस्टम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश अनुकूल वातावरण और युवा प्रतिभाओं को अवसर देने वाली नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में मात्र 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 24,000 से अधिक स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें 08 यूनिकॉर्न भी शामिल हैं। वर्ष 2017 से पहले देश के बॉटम थ्री में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित हो चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये से अधिक तथा 09 इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इसके साथ ही 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' पुस्तिका का विमोचन और 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री जी ने उद्यमियों को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीशिएशन, लेटर ऑफ इन्टेन्ट तथा 12 नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए भारत इनोवेटर्स एवं यू0पी0 स्टार्टअप फण्ड समर्थित ए0आई0एफ0 प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2014 से पूर्व पूरे देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर ढाई लाख से अधिक हो चुके हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेण्ड है। दुनिया की सबसे युवा कार्यशक्ति उत्तर प्रदेश के पास है और इसे कौशल विकास से जोड़कर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि प्रदेश के कुल स्टार्टअप्स में से 50 प्रतिशत से अधिक का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जो राज्य की आधी आबादी की बढ़ती सामर्थ्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि नवाचार और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम हैं।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि स्टार्टअप ईकोसिस्टम को केवल चुनिंदा बड़े शहरों तक सीमित न रखकर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोएडा में एआई, कानपुर में डीप टेक, लखनऊ में हेल्थ टेक, वाराणसी में टूरिज्म व क्रिएटिव टेक, पूर्वांचल में एग्रीटेक तथा बुन्देलखण्ड में डिफेन्स एवं ड्रोन टेक की असीम संभावनाएं हैं। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के पात्र स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने अतिरिक्त इन्सेन्टिव की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि वर्तमान में देश के कुल स्टार्टअप्स में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों से केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर रिसर्च और इनोवेशन का माहौल बनाने पर जोर दिया और बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को अलग से विशेष फण्ड उपलब्ध कराया है।

मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि आई0आई0टी0 कानपुर (मेडटेक व ड्रोन), एस0जी0पी0जी0आई0 तथा आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी उभरती तकनीकों को पूरा सहयोग दे रही है। प्रदेश में एक दर्जन से अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित व संचालित करने की दिशा में तेजी से कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 में सिडबी के साथ शुरू किए गए 'फण्ड ऑफ फण्ड' को और अधिक गति दी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर फण्ड का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप्स को भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर 'प्लग एण्ड प्ले' मॉडल पर स्पेस भी मुहैया कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति के चलते आज प्रदेश कर्फ्यू व उपद्रव से पूरी तरह मुक्त है। विगत 09 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, महिला कार्यबल की भागीदारी तथा बड़े उद्योगों की संख्या में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

रक्षाबंधन पर्व: बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से सशक्त बनता उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 28 अगस्त, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आयोजित 'बिटिया और बहना यू0पी0 का गहना-स्नेह बन्धन कार्यक्रम' में प्रदेशवासियों, बहनों और बेटियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए विचार व्यक्त किए कि रक्षाबंधन केवल रक्षासूत्र का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पर्व-त्योहारों की परंपरा में सामाजिक समरसता के साथ विकास और स्वावलंबन का भाव समाहित है। शास्त्रों के अनुसार 'श्रद्धावान लभते ज्ञानम्', जीवन में ज्ञान अर्जन हेतु बड़ों के प्रति श्रद्धा और सम्मान आवश्यक है। यह श्रद्धा विश्वास में, विश्वास आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता में और आत्मनिर्भरता अंततः विकास में परिवर्तित होती है।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में तैयार होने वाली लगभग 15 करोड़ राखियों से लाखों कारीगरों, हस्तशिल्पियों और श्रमिकों की आजीविका जुड़ी है। स्थानीय उत्पादों की खरीद से प्राप्त धन कारीगरों तक पहुंचता है, जो पुनः बाजार में आकर अर्थव्यवस्था को गति देता है। रक्षाबंधन सामाजिक रिश्तों के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। प्रदेश में संचालित 'मिशन शक्ति' अभियान बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है।

मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें, जूते-मोजे और स्वेटर उपलब्ध करा रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को कक्षा-8 से कक्षा-12 तक उच्चीकृत किया जा रहा है और यह सुविधा सभी विकासखंडों तक पहुंचाने के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्रमिकों के बच्चों के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए गए हैं, जिनमें बालिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018 में कैप्टन मनोज पाण्डेय सैनिक स्कूल, लखनऊ में बालिकाओं के प्रवेश का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका अनुसरण अब देशभर के सैनिक स्कूलों में हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि देश में महिलाओं की रोजगार भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सशक्त हुई है, जिससे बेटियां नीति निर्माण के स्तर पर आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 27 से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं नगरीय परिवहन की बसों में महिलाओं को एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ ही 29 अगस्त के उपरांत 60 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक माता के लिए परिवहन निगम की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी कोई चुनौती नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बड़े स्तर पर स्किलिंग को रोजगार और अवस्थापना विकास से जोड़कर उत्तर प्रदेश को देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से बेटियों को संबल दिया जा रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने की दिशा में कार्य जारी है। प्रदेश पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़कर लगभग 45 हजार पहुंच चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने छात्राओं को तकनीक के संतुलित उपयोग का परामर्श देते हुए निर्देशित किया कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता से सोचने-समझने की क्षमता, दृष्टि और मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। विद्यार्थी स्मार्टफोन का उपयोग डिजिटल लाइब्रेरी, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित रखें तथा प्रतिदिन इसके उपयोग का समय घटाएं। तकनीक पर अत्यधिक निर्भर रहने के स्थान पर पाठ्यक्रम से इतर ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी पुस्तकों के अध्ययन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जीवन में शुद्ध नीयत, स्पष्ट लक्ष्य और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर परिश्रम करते हुए प्रदेश और देश के विकास में सक्रिय योगदान दें।

इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने मुख्यमंत्री जी को राखी बांधी तथा प्रदेश के सभी जनपदों से माताओं-बहनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मलिहाबाद, उच्च प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर गोसाईगंज, भारत स्काउट एंड गाइड्स, द संस्कृति स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय मोहनलालगंज, ए0पी0 सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज तथा लखनऊ पब्लिक कॉलेज राजाजीपुरम सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों की छात्राएं उपस्थित रहीं।

ज्ञान, शोध और नवाचार का एकीकृत केंद्र बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालयः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 28 अगस्त, 2026 को जनपद गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पंचम स्थापना दिवस तथा सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने संस्थापकों की दूरदृष्टि को साकार करते हुए ज्ञान, चिकित्सा, कृषि, कौशल, शोध और नवाचार का एकीकृत केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्वविद्यालय को केवल डिग्री बांटने तक सीमित न रहकर समाज की वास्तविक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना होगा। कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का ज्ञान किसान, मरीज, उद्योग और युवाओं तक पहुंचे, तभी शिक्षा की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया तथा प्रो0 अनुकीर्ति राज द्वारा रचित पुस्तकों 'नेशन एण्ड एक्सप्रेशन' एवं 'अमृतकाल और राष्ट्रवाद' का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आयोजित यह समारोह श्रद्धा को विश्वास, विश्वास को आत्मनिर्भरता तथा आत्मनिर्भरता को विकास से जोड़ने का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के 'पंच प्रण' के संकल्प को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांच वर्ष पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित यह विश्वविद्यालय आज 03 विधाओं से बढ़कर 53 विषयों एवं पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। अब अगले चरण में शोध, नवाचार, स्टार्टअप, उद्योग सहभागिता और रोजगार सृजन को विश्वविद्यालय की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना होगा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1932 में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दो महाविद्यालय शासन को दान किए थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले महिला महाविद्यालय तथा महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना की। वर्तमान में यह परिषद 50 से अधिक संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य कर रही है और शीघ्र ही अपने शताब्दी महोत्सव की ओर अग्रसर होगी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित व्याख्यानमालाएं युवा पीढ़ी को महापुरुषों के मूल्यों से जोड़ने का कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत की समृद्ध ऋषि परंपरा, योग, आयुर्वेद और पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना समय की मांग है। 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' के भाव के साथ चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी और कृषि जैसे विभिन्न अनुशासनों के समन्वय से ही भविष्य की जटिल चुनौतियों का समाधान संभव है। प्रौद्योगिकी का वास्तविक ध्येय समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है। इसके तहत एआई आधारित निदान, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स तथा कृषि में प्रिसिजन फार्मिंग, ड्रोन तकनीक, मृदा परीक्षण, स्मार्ट सिंचाई, फूड प्रोसेसिंग और जलवायु अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान के डिजिटल दस्तावेजीकरण और साक्ष्य आधारित प्रमाणीकरण से इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि डबल इंजन सरकार द्वारा अवस्थापना विकास, सुदृढ़ कनेक्टिविटी, निवेश, एमएसएमई, ओडीओपी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से युवाओं के लिए व्यापक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को केवल जॉब सीकर बनने के स्थान पर 'जॉब क्रिएटर', इनोवेटर और समस्या समाधानकर्ता बनना होगा। शिक्षा की यात्रा केवल उपाधि तक सीमित न रहकर 'शिक्षा से कौशल, कौशल से क्षमता, क्षमता से अवसर, अवसर से नवाचार, नवाचार से उद्यमिता, उद्यमिता से रोजगार और रोजगार से आर्थिक विकास' के सूत्र पर आगे बढ़नी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और नवाचार के बड़े क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। कृषि छात्रों का शोध किसानों की आय बढ़ाने, मेडिकल व फार्मेसी का शोध ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक तकनीक इसे व्यापक बाजार से जोड़ने में सहायक बने। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के अनुरूप 'फ्यूचर रेडी' बनना होगा। सरकार, विश्वविद्यालय, उद्योग और युवाओं की सशक्त साझेदारी से ही ज्ञान और नवाचार को आर्थिक प्रगति में बदला जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि आगामी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के निरीक्षण हेतु संपूर्ण फैकल्टी और टीम को एकजुट होकर कार्य करना होगा, क्योंकि टीमवर्क ही सफलता का मूल आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

देवरिया में 305 करोड़ रुपये की लागत वाली 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 29 अगस्त, 2026 को जनपद देवरिया के सलेमपुर और भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्रों के लिए 305 करोड़ रुपये की लागत वाली 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, प्रमाण पत्र, आवास की चाभी तथा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इससे पूर्व, उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया, बच्चों को चॉकलेट वितरित कीं और जनपद की विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्म देखी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देवरिया विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। जनपद में बाईपास, फ्लाईओवर और सड़कों के चौड़ीकरण से कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो रही है। बेसिक शिक्षा को मजबूती देने के लिए 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है तथा कम्पोजिट व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का उच्चीकरण हो रहा है। इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि देवरिया अपनी आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय चेतना के लिए विख्यात रहा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब जनपद में महर्षि देवरहा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित है। पूज्य राघव बाबा जैसी विभूतियों की यह पावन धरा अब उपेक्षा से बाहर निकलकर समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा और रोजगार का अभाव था। पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों में चार दशकों तक जापानी इन्सेफेलाइटिस से 50,000 से अधिक मासूमों की असमय मृत्यु हुई। वर्तमान सरकार ने प्रभावी कदमों से मस्तिष्क ज्वर का पूर्ण उन्मूलन किया है और प्रदेश को 'बीमारू राज्य' की श्रेणी से बाहर निकालकर 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' की दिशा में स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अपराध और माफियाओं के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने से प्रदेश में सुरक्षित वातावरण बना है। राज्य में 16 करोड़ लोगों को पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी डिजिटल निगरानी लखनऊ से की जाती है। विगत नौ वर्षों में लगभग 9.50 लाख युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी नौकरी दी गई है तथा 3 करोड़ से अधिक युवाओं को एमएसएमई व ओडीओपी के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए 2 करोड़ टैबलेट वितरण के लक्ष्य के तहत 50 लाख से अधिक टैबलेट दिए जा चुके हैं और 25 लाख नए टैबलेट की प्रक्रिया गतिमान है। स्नातक अंतिम वर्ष के सभी पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 1 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें 36,000 पुलिस व सब-इंस्पेक्टर पद, 45,000 होमगार्ड पद तथा 30,000 अन्य विभागीय पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 13 लाख सफल यूपीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती का अधियाचन भेजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' संचालित है और प्रत्येक न्याय पंचायत में डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी गई है और 60 वर्ष से अधिक आयु की माताओं के लिए भी यह सुविधा लागू की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनहित के धन का सदुपयोग केवल विकास और जनकल्याण के लिए होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार में जेपीएनआईसी परियोजना पर निर्धारित बजट से अधिक व्यय के बावजूद कार्य अधूरा छोड़ा गया, जबकि इस धनराशि से युवाओं के रोजगार और बुनियादी ढांचे का विस्तार हो सकता था। सरकार ने राजकीय धन की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सलेमपुर और भाटपार रानी की नवीन परियोजनाएं क्षेत्र की कनेक्टिविटी, चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देंगी। भाटपार रानी क्षेत्र में आरओबी/फ्लाईओवर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के विकास हेतु भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देवरिया सहित पूरे प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, बेहतर विद्युत आपूर्ति और उन्नत सड़क तंत्र स्थापित हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों, युवाओं और सामान्य नागरिकों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण किया और स्थायी समाधान के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 29 अगस्त, 2026 को जनपद बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के साथ खड़ी है और किसी भी प्रभावित परिवार को राहत व सहायता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा के दौरान बलियावासियों के धैर्य और साहस की सराहना करते हुए उन्होंने प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने के लिए जनता का अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने स्वयं बांसडीह, बलिया नगर और बैरिया विधानसभा क्षेत्रों में कटान व जलप्लावन से प्रभावित इलाकों का स्थलीय व हवाई निरीक्षण किया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की है, ताकि हर पीड़ित परिवार को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से लगभग 26 जनपदों के 251 गांवों के 1.71 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 447 बाढ़ चौकियां स्थापित कर राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं और 1,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाढ़ शरणालयों में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ठोस आपदा प्रबंधन के चलते इस वर्ष बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या पहले के 36-40 जनपदों की तुलना में घटकर 26 रह गई है और जनहानि भी न्यूनतम रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नदियों के चैनलाइजेशन और आवश्यकतानुसार ड्रेजिंग की योजना पर कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से घाघरा नदी में ड्रेजिंग कराई जाएगी और उससे निकलने वाली सिल्ट का उपयोग तटबंधों को मजबूत करने में होगा। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर बोल्डर से ठोकर बनाकर कटान को रोका जाएगा, जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि सुरक्षित रह सके और उनकी कृषि आय में वृद्धि हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को लगभग 50 किलो सामग्री से युक्त विशेष राहत किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आटा, चावल, दाल, चना, चीनी, तेल, आलू, मसाले, साबुन, बिस्किट, सैनिटरी पैड, डेटॉल, टॉर्च, छाता और बाल्टी-मग शामिल हैं। यह सामग्री वाहनों के माध्यम से सीधे पीड़ितों के घरों तक पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जलभराव के बाद होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए क्लोरीन की गोलियों सहित मेडिसिन किट वितरित की जा रही है। सर्पदंश, श्वान दंश अथवा जंगली जानवरों के हमलों की स्थिति से निपटने हेतु सभी जिला अस्पतालों और सीएचसी पर एंटी-स्नेक वेनम तथा एंटी-रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा प्रभावित पशुधन के लिए टीकाकरण, दवाएं, चारा एवं भूसे की समुचित व्यवस्था की गई है तथा गर्भवती महिलाओं व बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विकास की सतत प्रक्रिया पर गोरखपुर : 130 करोड़ रुपये की 170 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 29 अगस्त, 2026 को गोरखपुर में नगर निगम एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 130 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने राप्तीनगर क्षेत्र में नवनिर्मित कल्याण मण्डपम का लोकार्पण किया तथा कार्यक्रम स्थल पर पौधरोपण भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास की प्रक्रिया को निरन्तर आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर महानगर को आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और नागरिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। कल्याण मण्डपम इसी विकास प्रक्रिया में 'ईज ऑफ लिविंग' का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राप्तीनगर में निर्मित कल्याण मण्डपम महानगर का छठवां कल्याण मण्डपम है। सामान्य एवं गरीब परिवारों के लिए महंगे होटलों में विवाह, मुण्डन संस्कार, पारिवारिक एवं सामाजिक आयोजन करना कठिन होता है, ऐसे में कल्याण मण्डपम उनके लिए एक उत्तम, सुविधाजनक और किफायती विकल्प है।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि इस कल्याण मण्डपम में 300 से 500 लोगों की क्षमता वाला बड़ा सभागार, एक छोटा सभागार, 06 अटैच कमरे और विशाल लॉन की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक इसे बुक कराकर सामाजिक, पारिवारिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग एक दशक पूर्व इस स्थान पर डेढ़ से दो मीटर तक गहराई थी, जिसे मिट्टी डालकर समतल किया गया। इच्छाशक्ति और बेहतर योजना से इस स्थान का कायाकल्प कर शानदार भवन तैयार किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 2.5 करोड़ रुपये विधायक निधि से तथा 70 लाख रुपये गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबा गम्भीरनाथ वॉर्ड के मानबेला, जंगल तुलसीराम पश्चिमी, जंगल तुलसीराम-बिछिया, माधवनगर मौजा जंगल बेनी माधव नम्बर-1 तथा उर्वरकनगर के नकहा आदि क्षेत्रों में कल्याण मण्डपम एवं कन्वेंशन सेण्टर विकसित किए गए हैं। महानगर में 03 अन्य कल्याण मण्डपम निर्माणाधीन हैं और नए भी स्वीकृत किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में इंसेफेलाइटिस से मासूम बच्चों की मौतों को लेकर भय का वातावरण रहता था। वर्ष 1977 से चली आ रही इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्वच्छता, उपचार, रोकथाम, टीकाकरण और जनजागरूकता के माध्यम से ठोस कार्य किए गए, जिससे आज इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज माफिया मुक्त प्रदेश बन चुका है। कानून को चुनौती देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रदेश भर में पर्व-त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि महिलाओं के सम्मान और सुविधा के लिए रक्षाबंधन पर लगभग 60 लाख महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी गई। अब 60 वर्ष से अधिक आयु की माताओं को भी परिवहन निगम की बसों में तीर्थ स्थलों सहित अन्य यात्राओं के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि स्नातक अंतिम वर्ष की 50,000 मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा और रोजगार की सुगमता के लिए स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आगामी 02 महीनों में प्रत्येक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जहां युवाओं को देश के साथ-साथ जापान, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों में रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक लगभग 05 लाख बेटियों का विवाह कराया जा चुका है, जिसमें 01 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के क्रम में अब तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और अगले एक वर्ष में 01 लाख अतिरिक्त नियुक्तियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि गोरखपुर में 4 व 6 लेन सड़कों का जाल, ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर, लिंक एक्सप्रेस-वे, विरासत गलियारा, खाद कारखाना और रामगढ़ताल का कायाकल्प शहर को नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है। रामगढ़ताल अब पर्यटन और फिल्म शूटिंग का केंद्र बन चुका है तथा गोड़धोइया नाला परियोजना से जलभराव की समस्या का समाधान हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगर निगम द्वारा सी0एम0 ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है तथा इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर व सीसीटीवी कैमरों से शहर की निगरानी और प्रशासनिक प्रबंधन को दक्ष बनाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन, रीजनल वायरोलॉजी सेण्टर, एम्स गोरखपुर और आसपास के जनपदों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से आमजन को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि जनता जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों से सतर्क रहे। सरकार किसी गरीब, दलित या वंचित का शोषण नहीं होने देगी और बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को आगामी 04 सितम्बर को पड़ने वाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे पूरी भव्यता, श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की।

बारह संकल्पों के साथ लखनऊ छावनी में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 30 अगस्त, 2026 को लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लगभग 101 करोड़ रुपये लागत की 12 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना गया तथा लखनऊ छावनी के विकास से सम्बन्धित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि लखनऊ छावनी परिषद में 101 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हो रहीं ये परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि स्वच्छ छावनी, बेहतर पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दिव्यांग बच्चों को समान अवसर, युवाओं को खेल मंच, सुव्यवस्थित यातायात व पार्किंग तथा आधुनिक छावनी निर्माण के 12 संकल्प हैं।

रक्षा मंत्री जी ने बताया कि लखनऊ छावनी परिषद, सेना, रक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग जगत और नागरिक मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। लखनऊ की प्रगति पूरे प्रदेश की गति से जुड़ी है और राज्य सरकार व रक्षा मंत्रालय के आपसी समन्वय से विकास की गति कई गुना बढ़ी है।

रक्षा मंत्री जी ने रेखांकित किया कि विकसित भारत का वास्तविक अर्थ हर बच्चे को शिक्षा, हर घर में शुद्ध जल और वंचितों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। छावनी क्षेत्रों में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू कर पूर्व के जी प्लस टू (तीन मंजिल) के स्थान पर स्टिल्ट प्लस ग्राउण्ड प्लस थ्री (पांच मंजिल) भवनों का प्राविधान किया गया है, जिससे परिवारों को अपनी आवश्यकतानुसार आवास विस्तार का अवसर मिलेगा।

रक्षा मंत्री ने बताया कि लखनऊ छावनी परिषद ने ब्रिटिश कालीन बाजारों के नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के नाम पर रखे हैं। रॉयल आर्टिलरी बाजार का नाम एकता बाजार, ब्रिटिश कैवलरी बाजार का नाम ऊदा देवी बाजार, ब्रिटिश इन्फैन्ट्री बाजार का नाम मातादीन वाल्मीकि बाजार व मंगल पाण्डे बाजार तथा कैनेडी मार्केट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है। यह परिवर्तन नई पीढ़ी को अपने ऐतिहासिक बलिदानों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर पर कहा कि विगत 09 वर्षों में प्रधानमंत्री जी तथा केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा तय की है। आज लखनऊ अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ-साथ स्मार्ट रोड, सी0एम0 ग्रिड और आउटर रिंग रोड जैसी सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित हो चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी और महाराजा बिजली पासी की गौरवशाली विरासत मौजूद है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत लखनऊ ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों के निर्माण का केन्द्र बन रहा है। शहर की पारम्परिक चिकनकारी कला के साथ-साथ यूनेस्को द्वारा लखनऊ के खानपान को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में मान्यता दी गई है।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से छावनी परिषद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की ए0आई0 आधारित व्यवस्था तथा विद्यालयों में अभ्युदय कोचिंग प्रारम्भ की जा रही है। वर्ष के अन्त तक गोमती नदी को पूरी तरह स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाने का लक्ष्य है, जिसमें सेण्ट्रल कमाण्ड का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ छावनी को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, जिससे सैन्यकर्मियों, पूर्व सैनिकों और सिविलियन नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय के प्रति प्रदेश सरकार की ओर से आभार जताया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व पहचान के संकट, अभाव, अराजकता और अव्यवस्था से जूझने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुका है। प्रदेश में डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 06 नोड्स तेजी से विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। देश की पहली रैपिड रेल और पहला वॉटर-वे प्रदेश में संचालित हुआ है। वर्तमान में 05 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 17 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा मेट्रो का व्यापक विस्तार हुआ है। लखनऊ मेट्रो के द्वितीय चरण की स्वीकृति के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सैनिक स्कूलों की शुरुआत वर्ष 1960 में डॉ0 सम्पूर्णानन्द जी ने की थी और वर्तमान में कई सैनिक स्कूल देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार कर रहे हैं। आज की ये परियोजनाएं लखनऊ छावनी परिषद को एक आदर्श छावनी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम सिद्ध होंगी।

बहराइच-नानपारा-नेपालगंज रोड रेलखण्ड के ब्रॉड गेज का लोकार्पण एवं 04 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 31 अगस्त, 2026 को जनपद बहराइच में बहराइच-नानपारा-नेपालगंज रोड रेलखण्ड के आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन अर्थात मीटर गेज/छोटी लाइन से ब्रॉडगेज/बड़ी लाइन में बदलाव) का लोकार्पण तथा 04 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम को केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित किया। कार्यक्रम में मित्र राष्ट्र नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा व बाढ़ त्रासदी में मृतकों के प्रति 02 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहराइच-नानपारा-नेपालगंज रोड रेलखण्ड का आमान परिवर्तन (ब्रॉडगेज नेटवर्क में बदलाव) और 04 नई ट्रेनों का शुभारम्भ इस सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। लगभग 730 करोड़ रुपये की लागत से 56 किलोमीटर लम्बे रेलखण्ड को ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ने का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हुआ है, जिससे रुपईडीहा और नेपालगंज रोड सहित पूरे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री जी ने नेपाल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि साझी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हैं। भगवान पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ, गोरखा से गोरखपुर और जनकपुर से अयोध्या तक दोनों देशों की सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा त्वरित सहायता पहुंचाई गई है और संकट की इस घड़ी में भारत पूरी मजबूती के साथ नेपाल के नागरिकों के साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज प्रारम्भ हुई 04 नई रेल सेवाओं में वाराणसी-बहराइच एक्सप्रेस (14213/14), वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस (115131/32), गोण्डा-बहराइच ट्रेन (75109/10) तथा मेमू/डेमू ट्रेन (75111/12) शामिल हैं। रुपईडीहा से सीधे वाराणसी तक रेल सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने में सुगमता होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि पटरी बड़ी होने से रास्ते, बाजार और विकास के अवसर भी बड़े होते हैं। रुपईडीहा और बहराइच का क्षेत्र देश का प्रवेश द्वार है, जिसे अब सीमांत छोर के बजाय विकास और सम्पर्क के प्रमुख केन्द्र के रूप में देखा जा रहा है। यह रेल कनेक्टिविटी उद्योग, व्यापार, रोजगार, कृषि और कतर्नियाघाट जैसे ईको-टूरिज्म केन्द्रों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग एक हजार वर्ष पूर्व महाराजा सुहेलदेव ने इसी पावन धरती पर विदेशी आक्रान्ता सैय्यद सालार मसूद गाजी को पराजित कर राष्ट्र की रक्षा की थी। आजादी के बाद उपेक्षित रहे इस गौरवशाली इतिहास को वर्तमान सरकार ने सम्मान देते हुए बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक निर्मित कराया है, जो भारत के स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश भर में रेलवे का तीव्र आधुनिकीकरण, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण और आमान परिवर्तन का कार्य आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण को गति प्रदान कर रहा है। बहराइच से खलीलाबाद तक नई रेल लाइन के साथ गोरखपुर- सिद्धार्थनगर- शोहरतगढ़-बलरामपुर-बहराइच और नेपालगंज रोड तक एक विस्तृत रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्तमान डबल इंजन सरकार में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़क और रेल नेटवर्क स्थापित हो रहे हैं। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज व बालार्क ऋषि अस्पताल, बलरामपुर व गोण्डा में मेडिकल कॉलेज, श्रावस्ती में एयरपोर्ट तथा आसपास के जिलों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि पूर्वांचल में कभी कहर बरपाने वाली जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी को प्रभावी कार्ययोजना, स्वच्छता और समयबद्ध उपचार से पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है, जिससे मासूम बच्चों की असमय मौतों पर प्रभावी रोक लगी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा लखनऊ से बहराइच के बीच 04 लेन मार्ग को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़क और रेल दोनों क्षेत्रों में हो रहा यह ढांचागत सुधार सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के साथ-साथ भारत-नेपाल के सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारम्भ

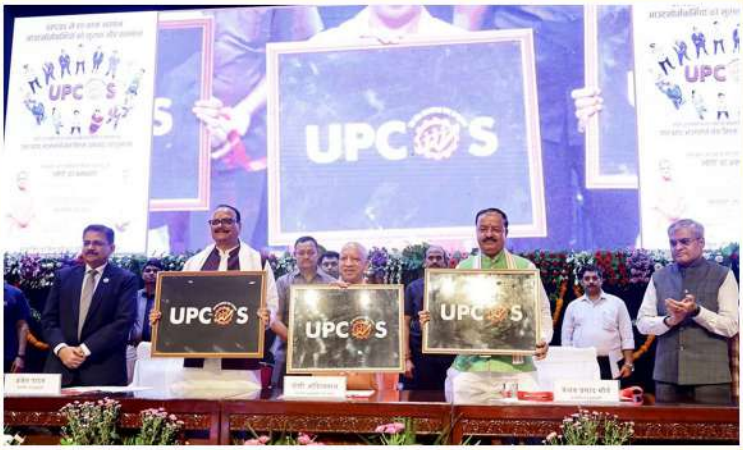

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 सितम्बर, 2026 को लोक भवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यू0पी0सी0ओ0एस0) का शुभारम्भ करते हुए कहा कि सरकार और कर्मचारी का सम्बन्ध केवल वेतन और कार्य का नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी का भी है। कर्मचारी का जीवन कागजों और कार्यालयों के चक्कर लगाने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए व्यतीत होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत का रिकॉर्ड सुरक्षित है, अधिकारों की रक्षा होगी और समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र क्रियाशील है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस निगम के माध्यम से प्रदेश के 03 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिकों और उनके परिवारों के लगभग 17 से 20 लाख लोगों के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने निगम की वेबसाइट, डिजिटल पोर्टल और 'लोगो' का अनावरण किया तथा आउटसोर्स कर्मियों को डेमो चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य सामाजिक सुरक्षा से सम्बद्ध ऐतिहासिक एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान भी सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षों की विकास यात्रा में सफाई कर्मियों, पम्प ऑपरेटरों, सचिवालय, चिकित्सालयों सहित शासन की समस्त व्यवस्थाओं से जुड़े प्रत्येक कार्मिक का अविस्मरणीय योगदान रहा है। सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि प्रत्येक कार्मिक को उसकी गरिमा के अनुरूप सम्मान और श्रम का उचित मूल्य मिले। आउटसोर्स सेवा निगम का मूल उद्देश्य इस संपूर्ण वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइज्ड, स्किल्ड, सिक्योर और डिग्निफाइड वर्कफोर्स में परिवर्तित करना है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि निगम के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शी, मेरिट आधारित और राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप होगी। पहले व्यवस्था कार्मिक, एजेंसी और सरकार के तीन अलग-अलग खेमों में बंटी थी, जहां कार्मिकों को समय पर मानदेय अथवा सेवा सुरक्षा की कोई निश्चित गारंटी नहीं मिलती थी। अब एक आधुनिक तकनीकी मंच से सभी पक्ष जुड़ेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त हो जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभागों में मैनपावर की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाकर समग्र ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाएगी। भर्ती, तैनाती, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस का डिजिटल प्रबंधन होगा। कर्मचारी अपने बैंक खाते, भुगतान और कटौतियों का सम्पूर्ण विवरण पोर्टल पर देख सकेंगे और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस पूरी व्यवस्था में नोडल अधिकारियों की जवाबदेही के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पूर्व में निर्धारित मानदेय से कम भुगतान की प्राप्त शिकायतों का स्थायी समाधान करते हुए पारिश्रमिक में लगभग दोगुना तक वृद्धि की गई है। अब शैक्षणिक योग्यता और पद की जिम्मेदारी के अनुरूप 20 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक का सम्मानजनक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। अब एजेंसियां मानदेय में कोई अनधिकृत कटौती नहीं कर सकेंगी और उनका सर्विस चार्ज सरकार द्वारा पृथक रूप से वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक माह का मानदेय अधिकतम 05 तारीख तक सीधे कर्मचारीके बैंक खाते में भेजा जाएगा तथा ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 का नियमित अंशदान जमा होगा। किसी भी कर्मचारी को सेवा सेमनमाने ढंग से नहीं निकाला जा सकेगा; इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन और शासन को पूर्व सूचना अनिवार्य होगी। यदि कोई शिकायत होगी तो नियमानुसार निष्पक्ष जांच के उपरांत ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व आउटसोर्स कर्मियों को मात्र बोझ समझा जाता था, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें राज्य का महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स और मूल्यवान एसेट मानती है। सुशासन की पहली शर्त संवेदनशीलता है और इसी दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं, अतः कर्मियों को भी पूर्ण निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई0एस0आई0 सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को आयुष्मान भारत जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई0एस0आई0 सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को आयुष्मान भारत जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। एस0बी0आई0 के साथ हुए समझौते के तहत आकस्मिक दुर्घटना की दशा में 20 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अग्निकाण्ड में 10 लाख, आकस्मिक दवा हेतु 05 लाख तथा एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पर 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किसी कार्मिक के साथ अनहोनी होने पर पीड़ित परिवार के पुत्र की शिक्षा हेतु 08 लाख, पुत्री की शिक्षा हेतु 10 लाख तथा दो पुत्रियों के विवाह हेतु 08 से 10 लाख रुपये तक की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मियों के जीरो बैलेंस खाते तथा परिवार के 04 सदस्यों को बैंक आधारित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित